देहरादून,पौड़ी–गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित | www.page3news.in | नगर संस्करण वर्ष 14 अंक: 300 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

पेज थ्री

देहरादून, शुक्रवार, 10 जनवरी 2020

विचार–प्रवाह...भारत में स्टार्टअप कल्चर

मौसम अधिकतम 17.0° न्यूनतम 5.0°

41452.35

2 ट्रंप के शांति संदेश पर ईरान की चुप्पी

7 सीएए के सपॉर्ट में कोच रवि शास्त्री

पाकिस्तानी दुष्प्रचार की निकाली हवा

जम्मू–कश्मीर के दौरे पर 15 देशों के राजनयिक

■पहले दिन सुरक्षाकर्मियों, सिविल सोसाइटी, स्थानीय मीडिया और नेताओं से की मुलाकात

स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के आतंकी खेल की खोली पोल

विदेशी राजनयिकों का दौरा शुक्रवार को भी जारी रहेगा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने इतना जरूर माना कि कुछ दिक्कतें हैं लेकिन व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। स्थानीय लोगों ने विदेशी राजनयिकों से साफ कहा कि जम्मू–कश्मीर के लोग पाकिस्तान को एक इंच भी धरती नहीं देंगे। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान पर जम्मू–कश्मीर में आतंकवाद फैलाने और लोगों की जान लेने का आरोप लगाया। उन्होंने विदेशी राजनयिकों से गुजारिश की कि वे पाकिस्तान पर दबाव बनाए ताकि वह जम्मू–कश्मीर में दखल न दे। विदेशी राजनयिक पाकिस्तान दुष्प्रचार के उलट घाटी में सामान्य हालात के गवाह बने।

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। जम्मू–कश्मीर में 5 अगस्त के बाद हालात तेजी से सामान्य हुए हैं। 15 देशों के राजनयिकों का एक दल वहां के हालात का जायजा लेने के लिए गुरुवार से 2 दिन के दौरे पर है। पहले दिन विदेशी राजनयिकों ने सिविल सोसाइटी, स्थानीय मीडिया और नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जम्मू–कश्मीर में रक्तपात के पाकिस्तानी दुष्प्रचार को सिरे से खारिज किया। विदेशी राजनयिकों से बातचीत में स्थानीय लोगों ने 5 अगस्त के बाद बिना किसी खूनखराबे के हालात को संभालने के लिए सरकार की खुलकर तारीफ की।

सिविल सोसाइटी, स्थानीय मीडिया और नेताओं से भी मिले राजनयिक: रवीश कुमार ने कहा कि राजनयिकों की पहली बैठक वहां के सुरक्षाकर्मियों के साथ हुई जिसमें सुरक्षा के हालात और आतंकवाद के खतरे के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद राजनयिकों ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों से बातचीत की जो पूरे जम्मू–कश्मीर से आए थे, हर क्षेत्र से थे।

कुमार ने बताया कि इसके बाद राजनयिकों ने स्थानीय मीडिया और नेताओं से मुलाकात की। किन–किन प्रमुख नेताओं से मुलाकात हुई? इस सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि दौरा अभी जारी है, शुक्रवार को दौरा पूरा होने के बाद पूरा विवरण दी जाएगी।

ईयू के प्रतिनिधिमंडल के जम्मू–कश्मीर नहीं जाने पर कुमार ने बताया कि ईयू के राजनयिक एक समूह में कश्मीर जाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भविष्य में ईयू राजनयिक भी कश्मीर का इस तरह दौरा कर सकते हैं।

राजनयिक खुद हालात देख सकें, दौरे का यही मकसदः एमईए

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने सरकार के सहयोग से 15 देशों के राजदूतों/उच्चायुक्तों के जम्मू–कश्मीर दौरे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने खुद देखा कि हालात सामान्य है। उन्होंने कहा कि विदेशी राजनयिकों ने यह भी देखा कि स्थानीय प्रशासन हालात सामान्य होने के लिए किस हद तक कोशिश कर रहा है। जिन 15 देशों के राजदूत/उच्चायुक्त जम्मू–कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, वे हैं– अमेरिका, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, मालदीव, मोरक्को, फिजी, नॉर्वे, फिलिपिंस, अर्जेंटिना, पेरू, नाइजर, नाइजीरिया, टोगो और गयाना।

नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण सस्पेंड

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) लखनऊ। सर्विस रूल का उल्लंघन करने के आरोप में गौतम बुद्ध नगर जिले के एसएसपी वैभव कृष्ण को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा 14 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिनमें वे पांच अधिकारी भी शामिल हैं, जिनके नाम एसएसपी वैभव कृष्ण की गोपनीय रिपोर्ट में शामिल थे। अब लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी को गाजियाबाद का एसएसपी बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक, एसएसपी वैभव कृष्ण का जो चौट वायरल हुआ था, उसे फरेंसिक रिपोर्ट में सही पाया गया है। आईपीएस वैभव कृष्ण ने इस विडियो को एडिटेड बताया था। वैभव कृष्ण ने वायरल विडियो के संबंध में खुद एफआईआर कराई थी।

राष्ट्रपति भवन को बढ़े जेएनयू के छात्र, हिरासत में

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। जेएनयू में हुई हिंसा के खिलाफ स्टूडेंट्स ने गुरुवार शाम राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च निकाला जिन्हें बीच में ही रोक लिया गया है। इस दौरान दोनों के बीच हाथापाई भी हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वीसी एम जगदीश कुमार को हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे थे जिन्हें आंबेडकर भवन के पास हिरासत में लिया गया है।

उधर, एचआरडी मंत्रालय के अधिकारियों और जेएनयू प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक समाप्त हो गई है। बैठक के बाद जेनयूएसयू की अध्यक्ष आइशी घोष ने कहा कि जब तक कुलपति एम जगदीश कुमार को नहीं हटाया जाता किसी भी तरह की बात नहीं होगी और मंत्रालय बात करना चाहता है तो यूनिवर्सिटी कैम्पस आए।

पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की भी खबर

उधर, जेएनयूएसयू ने ट्वीट कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। जेएनयूएसयू ने कहा, श्शाम के 6 बजे के बाद का वक्त है। क्या पुलिस बता सकती है कि कुछ महिला प्रदर्शनकारियों को कथित रूप से सूर्यास्त के बाद बिना किसी महिला अधिकारी की मौजूदगी के क्यों उठाया गया? 5 जनवरी को जेएनयू में हुई हिंसा के विरोध में देशभर में स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं।

बृहस्पतिवार को राजधानी दिल्ली में स्टूडेंट्स के साथ ही पॉलिटिकल पार्टियों ने मार्च निकाला। यह मार्च मंडी हाउस से एचआरडी मंत्रालय की तरफ निकाला गया जिन्हें शास्त्री भवन के पास रोक दिया गया।

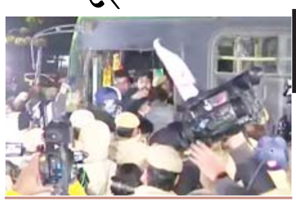

विरोध का छात्रों से कोई लेना–देना नहीं: करात

मंडी हाउस में जुलूस में शामिल बृंदा करात ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है और यह वो लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। वे फर्जी कहानियां बुन रहे हैं कि विरोध का छात्रों से कोई लेना–देना नहीं है बल्कि यह राजनैतिक है।श येचुरी ने कहा, श्तीन घंटे तक नकाबपोशों ने विश्वविद्यालय के छात्रों को पीटा। वे परिसर में घुसे तब पुलिस मुख्य द्वार पर मौजूद थी।

देश कठिन दौरे से गुजर रहा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को संवैधानिक घोषित करने की मांग कर रही याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस समय देश कठिन दौर से गुजर रहा है और बहुत अधिक हिंसा हो रही है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्य कांत की पीठ ने याचिका पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि पहली बार कोई किसी कानून को संवैधानिक घोषित करने का अनुरोध कर रहा है।

पीठ ने कहा कि वह हिंसा थमने के बाद सीएए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा, इस समय इतनी अधिक हिंसा हो रही है और देश कठिन दौर से गुजर रहा है और हमारा प्रयास शांति के लिए होना चाहिए।

इस कोर्ट का काम कानून की वैधता निर्धारित करना है न कि उसे संवैधानिक घोषित करना।

मांग

सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार

59 याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी

शीर्ष अदालत ने इस कानून को चुनौती देने वाली 59 याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और इसे जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया था। सीएए के तहत 31 दिसंबर, 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध समुदाय के सदस्यों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।

सीएए को संवैधानिक घोषित करने की मांग

जस्टिस ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब अधिवक्ता विनीत ढांडा ने सीएए को संवैधानिक घोषित करने और सभी राज्यों को इस कानून पर अमल करने का निर्देश देने के लिए दायर याचिका सुनवाई के लिए शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। इस याचिका में अफवाहें फैलाने के लिए कार्यकर्ताओं, छात्रों और मीडिया हाउस के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट 18 दिसंबर को सीएए की संवैधानिक वैधता की विवेचना के लिए तैयार हो गया था लेकिन उसने इसके अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

दिल्ली में आईएस मॉड्यूल का खुलासा, तीन संदिग्ध आतंकी अरेस्ट

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आतंकी संगठन आईएसआईएस के मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बृहस्पतिवार को तीन संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। तीनों को कथित रूप से आईएस का आतंकी बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आईएस के तीनों संदिग्ध 26 जनवरी से पहले दिल्ली–एनसीआर में हमले की फिराक में थे। बताया जा रहा है कि तीनों को विदेशी हैंडलर से निर्देश भी मिल रहे थे।

बता दें कि दिल्ली इन दिनों वैसे भी हाई अलर्ट पर है।

संक्षिप्त समाचार

निर्भया केसः दोषी विनय कुमार शर्मा ने दाखिल की क्यूरेटिव पिटिशन

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। निर्भया केस में दिल्ली की एक अदालत द्वारा डेथ वॉरंट जारी करने के कुछ दिन बाद ही चार में से एक दोषी विनय कुमार शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल की है। याचिका में फांसी पर रोक की मांग की गई है। बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 जनवरी को चारों दोषियों का डेथ वॉरंट जारी कर दिया था। हालांकि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की परंपरा रही है उसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले में ही शीर्ष अदालत ने क्यूरेटिव पिटिशन में अपना फैसला पलटा है। ऐसे में दोषियों की फांसी टलना मुश्किल लग रहा है।

कांग्रेस शासित 3 राज्यों में टैक्स फ्री हुई छपाक

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

भोपाल। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हिंसा के विरोध में कन्हैया कुमार के साथ जेएनयू पहुंचीं अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक को कांग्रेस शासित प्रदेशों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और और पुदुचेरी में टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया है। शुक्रवार को रिलीज होने जा रही यह फिल्म इन दिनों काफी विवादों में चल रही है। बीजेपी नेताओं और उनके समर्थकों ने जहां इस फिल्म का विरोध किया है।

कमलनाथ का मोदी पर वार, बाप–दादा सेनानी नहीं

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को राष्ट्रवाद का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी पर जमकर हमला किया। कमलनाथ ने कहा कि ये लोग कांग्रेस को और सेवा दल को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। आप अपने रिश्तेदार का तो बता दीजिए, अपना नाम तो छोड़िए, बाप–दादाओं का नाम तो छोड़िए...इनका कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं रहा और ये राष्ट्रवाद का पाठ कांग्रेस को पढ़ाने आते हैं।

Are you Planning to make a Website or already have ?
If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.

Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. I Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in